

प्रेषक,

एल0एम0 घन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अधिराशी अधिकारी,
नगर पंचायत,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 19 जनवरी, 2010

विषय:- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैर निर्वाचित निकायों के लिए अनुदान धनराशि का आवंटन। (चतुर्थ किस्त हेतु)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की निम्न 03 गैर निर्वाचित नगर पंचायतों को चतुर्थ किस्त के लिए उनके सामने अंकित धनराशि के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु रु० 1250000.00 (रु० बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार में)			
क्र० सं०	नगर पंचायत का नाम	चतुर्थ किस्त	कुल योग
1-	बद्रीनाथ	625	625
2-	केदारनाथ	375	375
3-	गंगोत्री	250	250
	योग:-	1250	1250

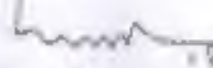
2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:-

- (1) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1874/XXVII(1)/2008, दिनांक 22 नवम्बर, 2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का ध्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- (2) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेगा तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगा। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महाप्रदेशाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेगा।



- (3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।
 - (4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।
 - (5) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
- 3- इस सम्बंध में होने वाला खय घालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-193-नगरपंचायत/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि-00-04-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान-20-सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता के नामे जाता जायेगा।


संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

 28/11/2010
 (एल०एम० पन्त)
 सचिव, वित्त

संख्या- 42 (4)/XXVII(1)/2010 एवं तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, बमोली, रुद्रप्रयाग।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, देहरादून।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, बमोली, रुद्रप्रयाग।
- 9- विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
- 10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 11- एन०आई०सी०, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

 28/11/2010
 (एल०एम० पन्त)
 सचिव, वित्त